

संख्या-¹⁷²⁹(बी)/क.नि.-6-2017-20(बी)-15/17

प्रेषक,

सी०एल० गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
संस्थागत वित्त, बीमा एवं,
वाह्य सहायतित परियोजना
महानिदेशालय, लखनऊ।

2. संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
लखनऊ, उ०प्र०।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, अनु०-6

लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2017

विषय- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के एन०पी०ए० में वर्गीकृत फसल ऋण हेतु एन०पी०ए० समाधान योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के एन०पी०ए० वर्गीकृत फसल ऋण के संबंध में एन०पी०ए० समाधान योजना के लागू किए जाने हेतु शासनादेश सं०-1523 बी/क.नि-6-2017-1(बी)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर-1 में यह व्यवस्था दी गयी है कि एन०पी०ए० समाधान योजना में सम्मिलित होने हेतु ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा अपने सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर योजना में विहित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि व्यावसायिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्तर से योजना स्वीकार किये जाने हेतु बैंकों के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के संबंध में अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

3. उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एन०पी०ए० समाधान योजना को व्यावसायिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाने के संबंध में अंतिम समय 30 नवम्बर, 2017 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्णय के अनुसार अग्रतेर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी०एल० गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1729 (बी)/क.नि.-6/2017/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/संस्थागत वित्त/आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/कृषि/सूचना, उ०प्र० शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
5. विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन (श्री नील रत्न)।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से

(सी०एल०
संयुक्त सचिव